सरकार की पहल बनी वरदान

अब 'चिरंजीवी' राजस्थान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार स्वस्थ और निरोगी राजस्थान के संकल्प के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। इन योजनाओं के जरिए आम जन को स्वास्थ्य बीमा के साथ-साथ साधारण और असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को आउटडोर एवं इंडोर चिकित्सा सुविधाएं पूर्ण रूप से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हार्ट सर्जरी, कॉकलियर इम्प्लांट, कैंसर, थैलेसीमिया एवं हीमोफीलिया जैसे असाध्य रोगों के मरीजों के लिए यह योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं।

लोगों को स्वस्थ होते देखना हर्ष का विषय

प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेकर स्वस्थ हो रहे हैं, यह हम सबके लिए हर्ष का विषय है। इस योजना से लाखों लोगों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। इस योजना के कारण राजस्थान स्वास्थ्य बीमा की कवरेज में देश में पहले पायदान पर है। जिन लोगों ने अभी तक चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अब अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कैशलेस इलाज मिल सके। राजस्थान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। केंद्र सरकार को भी राज्य की इन योजनाओं को अपनाना चाहिए।

-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

दिल में छेद का हुआ ऑपरेशन, मिला नया जीवन

बारां शहर के तेल फेक्ट्री क्षेत्र निवासी 8 वर्षीय बालिका दीया कुमारी को चलने में परेशानी होती थी और वह काफी बीमार रहती थी। जांच में पता चला कि उसके दिल में छेद है जिसके कारण वह बीमार रहती है और दिल के ऑपरेशन के द्वारा बालिका पुनः स्वस्थ हो सकती है। बच्ची के पिता जगदीश कुमार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, इस पर उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। योजना के तहत बालिका का सफल व निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद दीया कुमारी पूर्णतया स्वस्थ हो गई। बालिका के पिता जगदीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क ऑपरेशन हुआ और उन्हें अपनी जेब से कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ी।

बड़े इलाज भी योजना के दायरे में

बायपास सर्जरी हुई निःशुल्क

मजदूरी कर परिवार का जीवन यापन करने वाले सोहनलाल और उनके पूरे परिवार के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक वरदान साबित हुई। श्रीकरणपुर तहसील के रहने वाले 49 वर्षीय सोहनलाल मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। ब्लॉकेज की वजह से उन्हें बायपास सर्जरी के लिए बोला गया। निजी अस्पताल में लगभग ढाई लाख रुपए का खर्च बताया गया। परिवार को इतनी भारी भरकम राशि जुटाने की चिंता सताने लगी। जब उन्हें पता चला कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सारा इलाज निःशुल्क हो जाएगा तो परिवार की आर्थिक परेशानी की चिंता तुरंत दूर हो गई। ।

सोहनलाल ने बताया कि वे करीब एक साल से बीमार थे। दिल संबंधी परेशानी के कारण दिल बैठा हुआ था, खुद और पूरा परिवार परेशानी में था। पैसों की दिक्कत की वजह से उन्हें डर था कि ऑपरेशन हो पाएगा या नहीं, लेकिन चिरंजीवी से इलाज के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो गया है।

घुटना प्रत्यारोपण से जीवन हुआ आसान

श्रीगंगानगर की सादुलशहर तहसील के ग्राम हाथियांवाला निवासी 69 वर्षीय जसराज सिंह पिछले दस वर्षों से घुटनों के दर्द से पीड़ित थे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उन्होंने हनुमानगढ़ के निजी अस्पताल में इलाज के लिए संपर्क किया, जहां उनका घुटना प्रत्यारोपण किया गया। जसराज सिंह के घुटनों के दर्द और चलने-फिरने में दिक्कत की समस्या अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है और वे अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आए हैं।

जसराज ने बताया कि घुटना प्रत्यारोपण के लिए निजी अस्पताल में लगभग एक लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि चिरंजीवी योजना की वजह से उनका एक भी रुपया ऑपरेशन पर नहीं लगा।

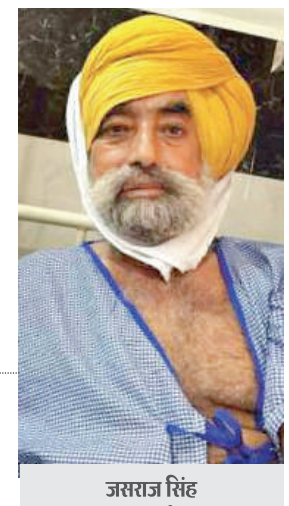

जसराज सिंह
-सादुलशहर, श्रीगंगानगर

कानों में गूंजी खुशियों की किलकारी

नागौर निवासी रजब अली की बेटी शकीना बचपन से सुन नहीं पाती थी। गांव के राजकीय अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच कर बताया कि शकीना कंजेनिटल डेफनेस यानि जन्मजात बहरेपन की बीमारी से ग्रसित है। इसके बाद बच्ची को उच्च स्तरीय जांच एवं उपचार के लिए जोधपुर के मथुरादास माथुर राजकीय अस्पताल में रैफर किया गया। यहां मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन होने के कारण शकीना का कैशलेस उपचार हुआ। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने शकीना के कॉक्लियर इम्प्लांट की तैयारी शुरू कर दी और आखिरकार 12 अक्टूबर, 2022 को उसका सफल ऑपरेशन किया गया।

कॉक्लियर मशीन की कीमत 10 लाख रुपए होने के बावजूद भी चिरंजीवी योजना में रजब अली को एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा।

रजब अली की बेटी शकीना
-नागौर

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हुआ इलाज, ताई ने किडनी डोनेट की...

निःशुल्क किडनी ट्रांसप्लांट से 35 वर्षीय जीतेंद्र को मिला नया जीवन

'बीमारी कभी पूछकर नहीं आती और जब आती है तो कई बार घर को कर्जदार कर जाती है। ऐसे में राजस्थान के लोगों के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क उपचार की जो व्यवस्था कर रखी है, वह अपने आप में अद्भुत है।'

चूरू जिले के निवासी जीतेंद्र के परिजनों का उक्त कथन राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सफलता का एक बड़ा प्रमाण है। चूरू जिले के तांबाखेड़ी गांव निवासी 35 वर्षीय जीतेंद्र पूनिया का किडनी ट्रांसप्लांट चिरंजीवी योजना के तहत जयपुर के संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल में पूर्णतः निःशुल्क हुआ।

सच्चे रिश्तों की मिसाल पेश करते हुए जीतेंद्र की 65 वर्षीय ताई संतोष देवी ने जीतेंद्र को अपनी किडनी डोनेट की। पूर्व में, वर्ष 2013 में भी जीतेंद्र को उनकी माता परमेश्वरी देवी ने अपनी किडनी डोनेट की थी। इसके बाद पिछले कुछ समय से फिर समस्या उत्पन्न होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जीतेंद्र के एक रिश्तेदार ने बताया कि जब वर्ष 2013 में गुरूग्राम के एक निजी अस्पताल में जीतेंद्र का किडनी का पहला ऑपरेशन हुआ तो इस पर करीब 10 से 12 लाख रुपए का खर्च आया था, जो उनके परिवार के लिए बहुत ही बड़ी राशि थी। लेकिन अब राज्य सरकार के सहयोग से उनका पूर्णतया निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है, इससे परिवार को आर्थिक चिंता से छुटकारा मिला है।

दूसरी ओर, एक अन्य मामले में धौलपुर की 54 वर्षीय मीना देवी को गले एवं सीने में दर्द की शिकायत थी। जयपुर के एक निजी अस्पताल में चिरंजीवी योजना के तहत मीना देवी की जांच में एलआरटीआई जैसी गंभीर बीमारी की पुष्टि हुई। आमतौर पर इस बीमारी के इलाज में लाखों रुपए का खर्च आता है और लोगों के घर-दुकान तक बिकने की नौबत आ जाती है। लेकिन मीना देवी को यह उपचार चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क मुहैया हुआ।

36 दिन तक चला प्री-मैच्योर बेबी का उपचार दो लाख रुपए का निःशुल्क इलाज हुआ

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्री-मैच्योर बेबी को मिला नवजीवन, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण परिवार के लिए बच्चे का महंगा इलाज संभव नहीं था...

चूरू जिला निवासी श्रीमती विनोद कंवर ने एक प्री-मैच्योर बच्चे को जन्म दिया। प्री-मैच्योर बेबी के पिता गजेन्द्र सिंह ने बताया कि बच्चे के जन्म पर निजी अस्पताल में कुल 40 हजार रुपए का खर्च हुआ था। पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बच्चे का आगे का इलाज कराना मुश्किल हो रहा था। इसके चलते लगने लगा था कि शिशु बच भी पायेगा या नहीं।

बाद में उन्होंने चिरंजीवी योजना में अधिकृत झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित निजी हॉस्पिटल में बच्चे को भर्ती करवाया। भर्ती करवाने के बाद बच्चे की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होता गया। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना से हमारे बच्चे को नवजीवन मिला है। प्री-मैच्योर बेबी का उपचार 36 दिन तक चला और लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आया। लेकिन योजना के तहत निःशुल्क उपचार के बाद अब उनका बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है और उन्हें आर्थिक रूप से भी राहत मिली है। जब बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया तब इसका वजन 740 ग्राम था, ऑर्गन डवलप नहीं हुए थे।

निःशुल्क हुआ उपचार

▪ चूरू जिला निवासी श्रीमती विनोद कंवर अपने बच्चे के साथ

बच्चे को निरंतर दवा दी गई, केयर की गई जिससे शिशु का वजन 1.26 किलो ग्राम हो गया। ऑर्गन डवलप होने तथा 36 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद नॉर्मल होने पर शिशु को डिस्चार्ज किया गया।

गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क इलाज • आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जीवनदायिनी बनी योजना...

इलाज के बड़े खर्च की चिंता से मुक्त हुए राजस्थान के लोग

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है जो लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से इलाज करवाने में सक्षम नहीं थे। पूरे राज्य में ऐसे हजारों मामले हर महीने सामने आ रहे हैं जिसमें इस योजना की वजह से पुरानी बीमारियों या दुर्घटनाग्रस्त लोगों का निःशुल्क इलाज हो रहा है।

जयपुर जिले के ठीकरिया गांव की रहने वाली गीता देवी के पति मनोज सेन के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और रॉड लगी। इसमें 40 हजार रुपए तक का उपचार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में निःशुल्क हुआ। गीता देवी ने बताया कि डॉक्टर से जब उन्होंने सलाह ली थी तो निजी अस्पताल में इस ऑपरेशन का खर्च करीब 1 लाख रुपए बताया गया था।

आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह इलाज कराने में अक्षम थीं। उन्हें गांव के लोगों से चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने ई-मित्र पर जाकर पंजीयन करवाया। इस योजना के कारण उनके पति का यह ऑपरेशन निःशुल्क हो सका। गीता देवी ने कहा कि यह योजना गरीब वर्ग के लिए जीवनदायिनी है।

इसी तरह, चिरंजीवी योजना से ही लाभ लेने वाले जयपुर के सांगानेर निवासी जगदीश प्रसाद शर्मा का कहना है कि इस योजना से उनकी आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन हो सका। राजस्थान सरकार की यह योजना गरीब और वंचित वर्ग के लिए बेहद उपयोगी है। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन इस योजना के कारण उनका सफलतापूर्वक उपचार हुआ और अब वे स्वस्थ हैं।

दूसरी ओर, बाड़मेर जिला निवासी नौ वर्षीया बालिका परमेश्वरी को योजना की बदौलत नई जिंदगी मिली। उसे गंभीर हृदय रोग था, जिसके इलाज का खर्च भारी-भरकम था। लेकिन उसे जोधपुर के अस्पताल में रेफर कर चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत उसकी सारी जांचें और सर्जरी निःशुल्क करवाई गईं। इस तरह की सर्जरी में 8 से 10 लाख का खर्च संभावित था जो इस योजना के चलते पूरी तरह से निःशुल्क हो गई।

जटिल बीमारियों का भी हो रहा निःशुल्क इलाज...

इस योजना में ब्लैक फंगस, कैंसर, पैरालाइसिस, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों का जटिल से जटिल इलाज भी बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है। ऐसे ही एक मामले में जयपुर की सोड़ाला निवासी सुशीला देवी को ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। उन्होंने इसके उपचार के लिए जब निजी अस्पताल में परामर्श लिया तो इसका खर्चा 5 से 7 लाख रुपए तक बताया गया। यह सुनकर सुशीला देवी और उनका पूरा परिवार चिंता से घिर गया। उन्हें जब चिरंजीवी योजना का पता चला तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराया।

उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल में चिकित्सक से परामर्श लिया। यहां चिरंजीवी योजना में उनका ऑपरेशन निःशुल्क किया गया तथा दवा सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए उन्हें एक भी रुपए खर्च नहीं करना पड़ा।

चिरंजीवी ने फिर भरे अन्नू के जीवन में शब्दों के रंग

दौसा के नांगलबैरसी की 14 वर्षीय अन्नू की 9 साल पहले दिमागी बुखार की वजह से हुए इन्फेक्शन के कारण सुनने और बोलने की क्षमता चली गई। बेटी को इस हाल में देखकर उसके परिजन काफी परेशान रहते थे और उसके पिता लगातार अपनी बेटी के इलाज के लिए प्रयासरत थे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने अन्नू का ऑपरेशन किया। उसके ब्रेन में ऑडिट्री ब्रेनस्टेम इम्प्लांट (एबीआई) कर उसकी जिंदगी में फिर से शब्दों के रंग भरे गए। ऑपरेशन के 2 माह बाद जैसे ही डॉक्टरों ने इम्प्लांट का स्वीच ऑन किया और ब्रेन में लगी मशीन से आवाज गई तो अन्नू चहक उठी और खिलखिलाने लगी।

निःशुल्क हुआ लीवर ट्रांसप्लांट

लीवर पूरी तरह खराब होने की जांच रिपोर्ट मिलने पर मुकेश जीने की आस पूरी तरह खो चुका था क्योंकि लीवर प्रत्यारोपण में खर्च होने वाली राशि उनके लिए वहनीय नहीं थी। लेकिन मुकेश के जीवन में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक देवदूत की तरह आयी। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सकों ने मुकेश की पत्नी बबीता से लीवर का एक हिस्सा डोनेट करवाकर मुकेश का लीवर प्रत्यारोपित किया।

▪ स्पेशल इनिशिएटिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

राजस्थान के 1.40 करोड़ परिवारों को मिल रही ₹25 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज का अनुपालन करते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

चिरंजीवी योजना के मुख्य बिन्दु

- **यह** देश के किसी भी राज्य की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना है। **राजस्थान** की लगभग 88% जनता बीमा से कवर।
- **राजस्थान** के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क उपचार हेतु 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा।
- **वर्तमान** में प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा परिवार योजना से जुड़े हैं।
- **इनमें** से लगभग 1 करोड़ 26 लाख निःशुल्क श्रेणी के परिवारों का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
- **45** लाख से अधिक मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ मिल चुका है।
- **योजना** से वर्तमान में 874 राजकीय एवं 849 निजी चिकित्सालय संबद्ध हैं, जिनके माध्यम से 1,798 पैकेजेज में पात्र परिवारों के मरीजों को कैशलेस उपचार दिया जा रहा है।
- **इस** योजना के अन्तर्गत संबद्ध अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण जैसे किडनी, लीवर एवं हार्ट, कॉकलियर इम्प्लांट, बोनमेरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है।
- **मुख्यमंत्री** चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना - परिवार में एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा राशि।
- **7613** परिवारों को दुर्घटना बीमा राशि से लाभान्वित किया गया है अब तक।

राजस्थान में निःशुल्क उपचार एक नजर में

- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल 1331 प्रकार की दवाइयां, 956 सर्जिकल एवं 185 सूचर्स सहित कुल 2,472 दवाइयां, सर्जिकल व सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 4,710 करोड़ रुपए व्यय किये गए।
- राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित हैं। दवाइयों की पूर्ण अनुपलब्धता होने पर राजकीय चिकित्सालयों की मांग अनुसार स्थानीय स्तर पर क्रय कर उपलब्ध करवाई जाती हैं। इन्डोर एवं आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करवाई जा रही है।

राज्य के हर वर्ग को मिल रही सुविधा

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत

- एसएमएस कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों में 1033, मेडिकल कॉलेज अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं आरयूएचएस में 689, राजमेस मेडिकल कॉलेज / जिला / उप जिला, सैटेलाईट चिकित्सालयों में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 37 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व डिस्पेन्सरी चिकित्सालयों में 15 प्रकार की एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 14 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 1296 करोड़ रुपए व्यय कर 31.95 करोड़ जांचे कर 11 करोड़ मरीजों को लाभान्वित किया गया।

जब तक सामर्थ्य है, राजस्थान की सेवा करता रहूंगा

राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। हमारी सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा को लागू कर एक क्रांति का सूत्रपात किया है। मैंने प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया है और फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने के लिए लागू की गई हमारी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत लाभान्वित परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है और इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण का खर्च सरकार वहन करती है। मेरा हर प्रयास राजस्थान और उसके लोगों के हित के लिए होगा। हैल्थ के क्षेत्र में हम राजस्थान को पूरे देश के सामने एक मील का पत्थर बनाकर ही दम लेंगे।

-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

राजस्थान सरकार ने बढ़ते इलाज के खर्चों को देखते हुए प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का केवल एक उद्देश्य है, स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक 1 करोड़ 40 लाख परिवार जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत अब तक 45 लाख से ज्यादा मरीजों का कैशलेस इलाज भी हो चुका है।

राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना साल 2021 में लागू की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस/निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता था। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया था। अब 2023-24 के लिए इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में परिवार में एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा परिवार जुड़ चुके हैं और 27 जून 2023 तक 5000 करोड़ से ज्यादा की राशि व्यय कर 45 लाख से अधिक मरीजों को कैशलेस उपचार का लाभ दिया जा चुका है।

दुर्घटना बीमा की राशि को बढ़ाकर दोगुना किया गया

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में प्रति परिवार रुपए 5 लाख का दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया गया। वर्ष 2023-24 से परिवार में एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में **परिवार की दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया।** 7613 परिवारों को दुर्घटना बीमा राशि से लाभान्वित किया जा चुका है।

सड़क दुर्घटना के 40 पैकेज बढ़ाए, चिरंजीवी योजना में पीड़ितों को मिलेगा फायदा

राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में और भी राहत दी है। सरकार ने रोड एक्सीडेंट के 40 और पैकेज बढ़ाए हैं। अब दुर्घटना में घायल व्यक्ति का बिना किसी पहचान एवं पात्रता के भी मुफ्त इलाज होगा। सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के 1798 पैकेज में से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार के लिए 222 पैकेज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट उपचार के लिए चिह्नित किए हैं। पूर्व में चिरंजीवी योजना में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के 182 पैकेज शामिल थे।

मौजूदा वक्त में राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 222 पैकेज कर दिया है। अब राज्य के बाहर का व्यक्ति भी यदि राजस्थान में दुर्घटना में घायल होता है, तो चिरंजीवी योजना के तहत बिना किसी पहचान एवं पात्रता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबद्ध निजी एवं राजकीय अस्पतालों में दुर्घटना के 72 घंटों तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार दिया जाएगा। गंभीर घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को योजना का लाभ देने के लिए स्वेच्छा से अपना नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र व बैंक खाता बताना होगा। वहीं सामान्य घायल को अस्पताल पहुंचाने पर प्रशस्ति पत्र देंगे।

जटिल रोग का इलाज भी शामिल

- योजना का दायरा बढ़ाते हुए कॉक्लियर इम्प्लांट रिप्लेसमेंट एवं डायबिटीज रोगियों के लिए पैकेज शामिल किए।
- मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए 42 करोड़ रुपए व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की है।
- कॉक्लियर इम्प्लांट रिप्लेसमेंट के लिए चार पैकेज का अनुमोदन किया गया है।
- टाइप-वन डायबिटीज रोगियों के लिए इन्सुलिन पम्प के पैकेज का अनुमोदन किया है।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत बढ़ते रोगीभार को देखते हुए मरीजों को सुगमता से समस्त चिकित्सा सुविधाएं देने तथा रोगियों की मेडिकल हिस्ट्री ट्रेक करने के लिए चरणबद्ध रूप से IT आधारित हैल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रभावी किया गया।

अंग प्रत्यारोपण से जुड़े 37 पैकेज योजना में

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े राज्य के निवासियों के लिए प्रदेश के बाहर सहित किसी भी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण कराने से संबंधित 37 पैकेज शामिल किए गए हैं। इसमें किडनी, लीवर, हार्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को शामिल किया गया है। इन पैकेज में ऑपरेशन संबंधित जांचें हो सकती हैं। गाइड लाइन में ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को अस्पतालों को भुगतान करना होगा। उसके बाद 60 दिन में बिल प्रस्तुत करने पर उनको सरकार द्वारा राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। योजना में रोगी व उसके एक सहयोगी के लिए राज्य से बाहर आने-जाने के लिए हवाई यात्रा का भी प्रावधान किया गया है। इसमें एक लाख तक या वास्तविक व्यय राशि, जो भी कम होगी, उसका भी पुनर्भरण किया जाएगा। जिन रोगियों ने गाइड लाइन जारी होने से पहले तथा 1 अप्रैल 2023 के बाद राज्य के बाहर किसी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण करवाया है तो उनको शिथिलता प्रदान करते हुए 60 दिन के भीतर बिल प्रस्तुत करने पर राशि का पुनर्भरण किए जाने का प्रावधान है।

अति आवश्यक होने पर पैकेज राशि का 50 प्रतिशत एडवांस

विशेष व अति आवश्यक परिस्थितियों में ट्रांसप्लांट मूल्यांकन कमेटी की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद राजस्थान स्टेट हैल्थ एंश्योरेंस एजेंसी के द्वारा रोगी के उपचार के लिए उपयुक्त पैकेज राशि की 50 प्रतिशत राशि एडवांस में दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

अब तक 1.48 करोड़ जांचें निःशुल्क

राज्य के 54 जिला, उप जिला, सेटेलाईट अस्पतालों में टेलीरेडियोलॉजी एक्सरे रिपोर्टिंग करवाई जा रही हैं। जिसके तहत 21.42 लाख एक्सरे इमेजो की रिपोर्टिंग की गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में नए अनुबंध अनुसार 30 जिला उप जिला सेटेलाईट अस्पतालों में आउटसोर्स मोड पर 40 विशिष्ट जांच हर श्रेणी के मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। विशिष्ट जांच सुविधा अन्तर्गत 1.48 करोड़ जांचें की गई हैं।

देश में अद्वितीय राजस्थान का स्वास्थ्य मॉडल

प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार, ऐसा कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान

स्वास्थ्य का अधिकार (राइट टू हैल्थ) कानून से राजस्थान में इलाज की तस्वीर बदलने वाली है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को राइट टू हैल्थ दिया गया है। कानून के तहत राज्य की संपूर्ण आबादी को सरकारी और चिह्नित निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य का अधिकार मिला है। कानून लागू होने से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अस्पतालों की जवाबदेही तय हो जाएगी। सरकारी अस्पतालों के साथ चिह्नित निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज मिलने से प्रदेश के हर नागरिक को बड़ा फायदा मिलेगा। कानून में शामिल प्रावधानों के तहत सरकारी के साथ मरीजों को रियायती दर पर जमीन लेने वाले मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित ट्रस्ट के माध्यम से संचालित व स्वेच्छा से योजना में शामिल होने वाले निजी अस्पताल में भी आपातकालीन स्थिति में निःशुल्क इलाज मिल सकेगा।

राइट टू हैल्थ के खास प्रावधान

1. आउटडोर और इंडोर भर्ती मरीज सहित डॉक्टर को दिखाना और परामर्श, दवाइयां, जांच, इमरजेंसी परिवहन एम्बुलेंस, प्रोसीजर और सर्विसेज सहित इमरजेंसी इलाज की सभी सुविधाएं मिलेंगी।
2. डॉक्टरों की ओर से दिए जा रहे इलाज की संपूर्ण जानकारी मरीज और उसके परिजनों को जब चाहेंगे, तब मिलेगी।

3. आपातकाल की स्थिति में चिह्नित निजी अस्पताल तुरंत इलाज करेंगे। कोई मरीज पैसा देने में असमर्थ होगा तो भी उसे इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा। सरकार उसका पुनर्भुगतान करेगी। रैफरल की स्थिति में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाना भी अधिकार में शामिल है।
4. मेडिको लीगल मामले में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पुलिस की 20 एनओसी या पुलिस रिपोर्ट मिलने के आधार पर इलाज में देरी नहीं कर सकेंगे।
5. सर्जरी, कीमोथैरेपी की पहले से ही सूचना देकर मरीज या उसके परिजनों से सहमति ली जाएगी।
6. हर तरह की सर्विस और सुविधा की रेट और टैक्स के बारे में सूचना पाने का हक मिलेगा।
7. निजी अस्पताल मरीजों की बीमारी को सार्वजनिक नहीं करेंगे, केवल मरीज और उनके परिजनों को ही जानकारी दी जाएगी।
8. इस बिल में मरीज और उनके परिजनों को लेकर भी कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टरों के साथ मरीज या उनके परिजन दुर्व्यवहार नहीं कर सकेंगे।
9. प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा का लक्ष्य।

आप भी ले सकते हैं इस सुविधा का लाभ...

दरअसल, राजस्थान सरकार की ओर से दी जाने वाली ये सुविधा एक तरह से हैल्थ इंश्योरेंस है। इसका लाभ लेने के लिए आप खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए ई-मित्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत फ्री इलाज की सुविधा सरकार की ओर से दी जाती है। राजस्थान का प्रत्येक परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है। अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जन आधार नामांकन करवाना होगा। इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/ है।

इस योजना में पंजीकरण हेतु निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी...

- जन आधार कार्ड अथवा जन आधार के पंजीकरण रसीद का नंबर।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- परिवार के सभी सदस्यों का नाम और उम्र।

▪ स्पेशल इनिशिएटिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचा हुआ मजबूत

राज्य में हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाकर लोगों को सहज, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध करवाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से राजस्थान आज चिकित्सा सुविधाओं के साथ चिकित्सा शिक्षा में भी अग्रणी बन गया है।

जयपुर में बन रहा देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टॉवर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार प्रदेश में हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। इसके लिए सरकार ने पिछले करीब साढ़े चार साल में अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में देश के सबसे ऊंचे अस्पताल का निर्माण करवा रही है। लगभग 588 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस आईपीडी टॉवर का शिलान्यास पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। इस टॉवर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

आईपीडी टॉवर के शिलान्यास के साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में एक नई शुरुआत हुई है। यह आईपीडी टॉवर अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाओं से युक्त होगा। करीब 24 मंजिला इस अस्पताल में 1200 बैड की क्षमता होगी। वर्ष 2023-24 में आईपीडी टॉवर के लिए उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 160 करोड़ रुपए तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्डियोलॉजी में उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है।

एयर एंबुलेंस के लिए हेलीपैड

आईपीडी टॉवर में हेलीपैड से लेकर अत्याधुनिक ओटी, सुपर लग्जरी कॉटेज समेत तमाम सुविधाएं होंगी। 1200 बैड्स में 792 जनरल, 150 कॉटेज, 166 आईसीयू और 92 प्रीमियम बैड होंगे। इसके अलावा डबल बेसमेंट पार्किंग, मरीज परिजन के लिए दो बड़े वेटिंग हॉल, मेडिकल साइंस गैलेरी, 20 ऑपरेशन थिएटर, फूडकोर्ट के अलावा रेडियो और माइक्रोबायोलॉजी जांच संबंधित एडवांस लैब होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेज में पूरा किया जा रहा है।

देश में अपनी तरह का यह पहला टॉवर होगा, जहां अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एसएमएस अस्पताल में आउटडोर मरीजों की संख्या प्रतिदिन करीब 15 हजार है, ऐसे में इसके बनने के बाद इलाज के लिए एसएमएस आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी और उन्हें समस्त सुविधाएं एक बिल्डिंग में उपलब्ध होंगी।

सवाई मानसिंह अस्पताल में 24 मंजिला आईपीडी

₹588 करोड़
की अनुमानित लागत से निर्माणाधीन

- 100 ओपीडी पंजीकरण काउंटर
- दो मंजिला भूमिगत पार्किंग
- 1200 बैड और 20 ओटी
- टॉवर की छत पर गंभीर मरीजों के लिए एयर एंबुलेंस हेलीपैड

राजस्थान का सुदृढ़ हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर

- विगत वर्षों में वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न अस्पतालों में बैड्स की संख्या में 6 हजार 705 बैड्स की वृद्धि की गई।
- गहलोत सरकार ने विगत वर्षों में आधारभूत चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बेहतरीन कार्य किया है। प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं से लेकर सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का पूरे राज्य में विस्तार किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2023-24 के अनुसार 380 नए बैड्स की व्यवस्था और की जानी प्रस्तावित है।

43 ट्रॉमा सेंटरों की स्थापना की गई पिछले साढ़े चार साल में।

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले बजट को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर **7 प्रतिशत** तक किया है जो कि देश में सबसे ज्यादा है।

सभी जिलों में अब मेडिकल कॉलेज तथा राजकीय नर्सिंग कॉलेज

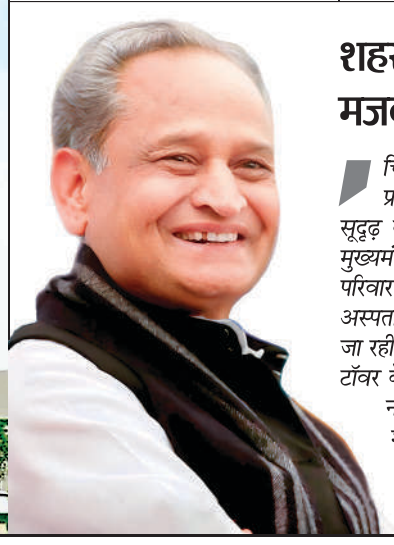

शहरों से लेकर हर गांव-ढाणी तक मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा सुदृढ़ बनाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश के हर परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। जयपुर में अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाओं से युक्त आईपीडी टॉवर के शिलान्यास के साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में एक नई शुरूआत हुई है। राज्य सरकार का मकसद है कि प्रदेश में शहरों से लेकर हर गांव-ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों।

-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

प्राइमरी एवं सेकेंडरी हैल्थ केयर सेवाओं को दी मजबूती

राज्य सरकार ने आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करते हुए अब तक 1002 नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा 365 उप स्वास्थ्य केंद्रों को पीएचसी में तथा 211 पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जा चुका है।

प्राइमरी हैल्थ केयर सिस्टम को और मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार 570 नए सब सेन्टर्स, 336 पीएचसी एवं 118 सीएचसी खोले जा रहे हैं। इसी प्रकार सेकेंडरी हैल्थ केयर सेवाओं का विस्तार करते हुए वर्तमान सरकार द्वारा 8 सैटेलाइट, 41 उपजिला व 21 जिला अस्पताल स्थापित किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में 2 सैटेलाइट, 26 उपजिला एवं 6 जिला अस्पताल और स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।

मेडिकल सीट्स में की बढ़ोतरी

गहलोत सरकार ने चिकित्सा संस्थानों के सफल संचालन के लिए चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया है। राजकीय क्षेत्र में वर्ष 2018 में जहां 1 हजार 850 एमबीबीएस सीटें थीं, वह वर्ष 2022 में बढ़कर 3 हजार 330 हो गयी हैं। गत चार वर्षों में राजस्थान में एमबीबीएस की सीटों में लगभग 80 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। आगामी वर्ष तक यह संख्या बढ़कर 3 हजार 830 हो जाएगी। राज्य में पीजी सीट्स की संख्या में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2018 में 960 पीजी सीट्स थीं जो बढ़कर 1690 हो गयी हैं अर्थात 76 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में बैड्स की संख्या लगातार बढ़ाई...

अस्पतालों में 6705 बैड्स की वृद्धि हुई, इस मामले में कई राज्यों से आगे निकला राजस्थान

प्रदेश सरकार के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में बैड्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विगत वर्षों में राज्य के चिकित्सा संस्थानों में 6 हजार 705 बैड्स की वृद्धि की गई है जबकि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूरे 5 वर्ष में मात्र 875 बैड्स की ही व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2023-24 के बजट की घोषणा के क्रम में 380 नए बैड्स की वृद्धि और की जानी प्रस्तावित है।

प्रति 1 लाख जनसंख्या पर हॉस्पिटल बैड्स की संख्या के मामले में राजस्थान - केरल, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, यूपी, पंजाब जैसे राज्यों से बहुत आगे है। राजस्थान में जहां प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर राजकीय चिकित्सा संस्थानों में लगभग 151 बैड उपलब्ध हैं वहीं उत्तरप्रदेश में यह संख्या लगभग 32, मध्यप्रदेश में 61, गुजरात में 65, बिहार में 21 और केरल में भी 118 ही है। आधारभूत चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का ही परिणाम है कि आज राजस्थान देशभर के राज्यों में विभिन्न स्तर के चिकित्सा संस्थानों के कार्यशील होने के मामले में अग्रणी राज्य हो गया है। भारत सरकार के आई.पी.एच.एस. नार्म्स से भी ज्यादा सब-सेंटर, पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल राजस्थान में खोले जा चुके हैं।

आज राजस्थान में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 12 सीएचसी, उपजिला तथा सैटेलाइट अस्पताल उपलब्ध हैं। निजी चिकित्सा संस्थानों को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या में लगभग 20 सीएचसी, उपजिला तथा सैटेलाइट स्तर के चिकित्सा संस्थान उपलब्ध हैं।

राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2023-24 की घोषणा के क्रम में 380 नए बैड्स की व्यवस्था और की जानी प्रस्तावित है।

प्रति 1 लाख जनसंख्या पर हॉस्पिटल बैड्स की संख्या के मामले में राजस्थान अन्य राज्यों से आगे...

डॉक्टरों की कमी हुई दूर

वर्तमान सरकार द्वारा चिकित्सा संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए अब तक 4496 चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। 5649 चिकित्सकों को विभिन्न पदों पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। 172 दंत चिकित्सकों की सीधी भर्ती शीघ्र होने वाली है। वहीं, विभिन्न अस्पतालों में चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों पर यूटीबी पर लगाए गए 463 चिकित्सकों की सेवा अवधि 31 दिसंबर 2023 तक या नियमित भर्ती से कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो तक बढ़ा दी गई है। नवसृजित चिकित्सा संस्थानों के लिए 500 चिकित्साधिकारी यूटीबी पर लगाए जाएंगे।

पैरामेडिकल के लगभग 20 हजार 546 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। यह भर्ती होने तक पैरामेडिकल के 5 हजार पदों को यूटीबी पर भरने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रांसफर, पोस्टिंग एवं सेवा/संस्थापन संबंधी अन्य कार्यों में पारदर्शिता के लिए राजहैल्थ पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। हाल ही में 1763 नवीन चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति इस पोर्टल के माध्यम से ही दी गई है।

हर जिले में खोले जा रहे हैं नर्सिंग कॉलेज

राजस्थान के सभी जिलों में राजकीय नर्सिंग कॉलेज प्रारम्भ किए जा रहे हैं। साल 2018 तक प्रदेश में राजकीय क्षेत्र में मात्र 10 नर्सिंग कॉलेज संचालित थे। वहीं, गत चार वर्षों में कुल 26 नए नर्सिंग कॉलेज खोले गए, जिससे 1560 नर्सिंग सीटों में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही बजट घोषणा 2023-24 में चार अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज अजमेर के मसूदा में व चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा तथा रावतभाटा व नागौर के नावां में राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में राजकीय क्षेत्र में कुल नर्सिंग सीटों की संख्या बढ़कर 2630 हो जाएगी।

सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हैल्थ कॉलेज

सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हैल्थ कॉलेज खोले जा रहे हैं। जयपुर में सत्र 2021-22 में मास्टर्स इन पब्लिक हैल्थ कोर्स आरयूएचएस में संचालित कॉलेज में 25 सीटों के साथ प्रारम्भ किया गया। जोधपुर एवं उदयपुर में सत्र 2022-23 से शुरू किया गया। शेष चार संभागों में अगले सत्र में कोर्स प्रारम्भ होगा, जिससे प्रतिवर्ष 175 छात्र लाभान्वित हो सकेंगे।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का किया गठन

मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए सरकार का मानवीय निर्णय

मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम-2017 एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम-2018 की पालना में राजस्थान में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है। जल्द ही मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठक आयोजित कर राज्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नियम और उपनियम बनाए जाएंगे। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड भी गठित किए जाएंगे। मानसिक रोगियों के अधिकारों संबंधी नियमावली भी निर्धारित की जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य सचिव अध्यक्ष, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक जनस्वास्थ्य को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। साथ ही इस प्राधिकरण में इनके अलावा पदेन एवं गैर सरकारी सदस्य भी होंगे।

यहां भी सुविधाओं में हुआ विस्तार

- राज्य के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में पीडियाट्रिक आईसीयू और नियोनेटल आईसीयू बैड्स की संख्या 600 से बढ़ा कर 2600 की गई है, जिसके परिणामस्वरूप शिशु मृत्युदर के अंकों में बेहतरीन सुधार हुआ है।
- राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में दैनिक क्षमता 16,037 सिलेण्डर के कुल 121 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं।

चिकित्सा शिक्षा • वर्तमान में 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, इस वर्ष 5 नए कॉलेज प्रारंभ होंगे...

राजस्थान के प्रत्येक जिले में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेज

राजस्थान देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां प्रत्येक जिले में एक मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। अब राज्य के प्रत्येक जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ राजकीय नर्सिंग कॉलेज की सुविधा भी राज्य के निवासियों को उपलब्ध हो रही है। राज्य में वर्तमान में 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। मेडिकल कॉलेज श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर में 100-100 सीटों के साथ प्रारम्भ कर दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज अलवर, बूंदी, करौली, हनुमानगढ़ और दौसा के लिए एलओपी प्राप्त हो गई है और इस वर्ष ये 5 मेडिकल कॉलेज और प्रारम्भ हो जाएंगे।

इनके अलावा वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित प्रतापगढ़, राजसमंद और जालौर सहित 10 मेडिकल कॉलेज और स्वीकृत किए जा चुके हैं जो कि विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं। राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालौर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया था, किन्तु भारत सरकार द्वारा यहां मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं करने पर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपने वित्तीय स्त्रोतों से इन जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। राजस्थान में निजी क्षेत्र के 9 मेडिकल कॉलेज हैं और राज्य सरकार निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति लाने पर भी काम रही है।

राजस्थान में 50 लाख लोगों पर दो सरकारी मेडिकल कॉलेज

- राजस्थान में प्रति 50 लाख की जनसंख्या पर 1.99 या कहें लगभग 2 राजकीय मेडिकल कॉलेज की उपलब्धता है।
- निजी मेडिकल कॉलेजों को शामिल करते हुए यह संख्या लगभग 2.5 होती है जबकि उत्तरप्रदेश में मात्र 0.8 या कहें 1 से भी कम, मध्यप्रदेश में 0.76 है।
- वहीं, तमिलनाडु में 0.88 गुजरात में 1.41 मेडिकल कॉलेज ही प्रति 50 लाख जनसंख्या पर उपलब्ध हैं।

सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को दिया बढ़ावा...

गहलोत सरकार ने राजस्थान के चार शहरों में शुरू किए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सभी संभागीय मेडिकल कॉलेजों में एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रो-सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, ओंको-सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और कार्डियोलॉजी की सुविधा प्रारम्भ की है। साथ ही राजमेस द्वारा संचालित 7 मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी की सुविधाएं स्वीकृत की गयी हैं।

राज्य में चार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य कैंसर संस्थान, जयपुर में प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2023-24 के बजट में एसएमएस, जयपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ हार्मोन एण्ड मेटाबोलिक डिसऑर्डर, इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी तथा आरयूएचएस के अन्तर्गत सेन्टर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबीलिटेशन के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पेरेटरी डिजीजेज स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिन पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। संभाग स्तरीय मेडिकल कॉलेजों में कैंसर के इलाज के लिए उच्च स्तरीय तकनीक की लीनियर एक्सीलेटर मशीनें स्थापित की जा रही हैं। जयपुर और जोधपुर में डीएसए मशीन मस्तिष्क रोगों के निदान के लिए स्थापित की गई है। एसएमएस, जयपुर में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है तथा जोधपुर में इस वर्ष प्रारम्भ किया जाना प्रक्रियाधीन है। नवीन चिकित्सा संस्थानों की स्थापना तथा उच्च स्तरीय मशीनों के उपयोग से कई दुर्लभ एवं असाध्य रोगों का इलाज कर मरीजों का जीवन सुगम किया गया है, इसके अन्तर्गत जयपुर में मेडिसिन विभाग में बोनमेरो ट्रांसप्लांट तथा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में ओपीडी में बोनमेरो ट्रांसप्लांट सम्पन्न किया गया।

▪ स्पेशल इनिशिएटिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विस्तार के लिए निरन्तर महत्वपूर्ण फैसले लिए

आधुनिक जीवनशैली में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी सहित अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की प्रासंगिकता और बढ़ी है। इन सभी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए हमारी राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। हमने अलग-अलग शहरों में नए औषधालय व चिकित्सालय बनाए, आयुर्वेद दवाओं के निर्माण पर जोर दिया, नए महाविद्यालय खोलने समेत हर स्तर पर कार्य किया। अब औषधालयों व चिकित्सालयों में सभी मरीजों को ओपीडी व आईपीडी की निःशुल्क सुविधा मिल रही है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए हमने राज्य में पहली बार आयुष नीति भी लागू की।

-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

राजस्थान में आयुष चिकित्सा सुविधाओं का हुआ बड़े स्तर पर विकास

गहलोत सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को दिया बढ़ावा, राज्य आयुष नीति लागू की, नए संस्थान शुरू किए

सरकार इसलिए लाई आयुष नीति

- आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संरक्षण और उपचार की गुणात्मक सेवाएं प्रदान करना और स्वास्थ्य सुविधाओं को उनकी पहुंच में लाना।
- आयुष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर करना, अपडेटेड पाठ्यक्रम बनाना और आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना।
- लोगों को सुरक्षित, सस्ती व उच्च गुणवत्तापूर्ण आयुष औषधि उपलब्ध करवाना।
- गुणवत्तापूर्ण औषधि निर्माण के लिए जड़ी बूटियों का संरक्षण, उत्पादन और घरेलू उपयोग व निर्यात के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जीवनशैली से जुड़े रोगों और क्रॉनिक डिजीज के लिए प्रभावी आयुष चिकित्सा विकसित करना एवं उपलब्ध आयुष औषधियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना।
- आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति लोगों में जागरुकता लाना। आयुष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्रों की सहभागिता को स्वीकार्य बनाना।

मजबूत हुआ आयुष चिकित्सा माध्यम

- राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से आम लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 122 चिकित्सालय एवं 3562 औषधालय, होम्योपैथिक चिकित्सा के 06 चिकित्सालय एवं 188 औषधालय, यूनानी चिकित्सा के 11 चिकित्सालय एवं 120 औषधालय संचालित हैं।
- वहीं, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के 3 चिकित्सालय एवं 3 औषधालय तथा जिला चिकित्सालयों में 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र संचालित हैं।
- इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत 1013 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष चिकित्सा केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।
- दूरस्थ क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा सेवा के लिए आयुर्वेद की 14 चल चिकित्सा इकाइयां तथा होम्योपैथिक की 2 चल चिकित्सा इकाइयां संचालित की जा रही हैं।
- राज्य में आयुर्वेद के 11680 चिकित्सक, होम्योपैथिक के 9402 चिकित्सक तथा यूनानी के 1250 चिकित्सक एवं 234 योग व प्राकृतिक चिकित्सक पंजीकृत हैं।

आयुष औषधालयों में भी ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएं निःशुल्क

राजस्थान के सभी श्रेणी के आयुष औषधालयों और चिकित्सालयों में उपलब्ध ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएं प्रदेशवासियों को पूर्णतः निःशुल्क दी जा रही हैं। योजना को औपचारिक रूप से 1 मई 2022 से शुरू किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुसार, आयुष विभागान्तर्गत संचालित चिकित्सा केंद्रों में भी ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएं निःशुल्क की गईं। मरीजों से किसी भी प्रकार का पंजीयन शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी में आने वाले तथा आईपीडी में भर्ती मरीजों को समस्त दवाइयां एवं जांचें निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। यह सुविधा राज्य के समस्त प्रदेशवासियों के लिये निःशुल्क उपलब्ध है।

225 ब्लॉक मुख्यालयों पर खुलेंगे नवीन होम्योपैथिक औषधालय

राजस्थान सरकार ने राज्य के 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा इनके संचालन के लिए 450 नये पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के अनुसार, 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोले जाएंगे। प्रत्येक औषधालय में एक होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी एवं एक कनिष्ठ नर्स/कम्पाउंडर को नियुक्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा और सुदृढ़ होगा एवं लोगों को स्थानीय स्तर पर होम्योपैथिक उपचार उपलब्ध हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में प्रत्येक ब्लॉक में होम्योपैथिक औषधालय खोलने की घोषणा की थी।

स्वस्थ राजस्थान

गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए सेवाएं...

राजस्थान सरकार आंचल प्रसूता केंद्र, पंचकर्म चिकित्सा केंद्र और जरावस्था चिकित्सा केंद्रों का भी संचालन कर रही है, जिसके माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। इसका फायदा विशेषकर गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्गों को हो रहा है। आंचल प्रसूता केंद्र के माध्यम से राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में आयुर्वेद चिकित्सा की महती भूमिका है। प्रत्येक संभाग एवं जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के आयुर्वेद चिकित्सालयों में चरणबद्ध तरीके से राज्य के प्रत्येक जिले में 35 आंचल प्रसूता केंद्र स्थापित किये गये हैं। इन केंद्रों पर गर्भिणी/प्रसूताओं के लिये विशेष औषधि एवं पथ्य (आहार) का वितरण कर उनके स्वास्थ्य का रक्षण किया जा रहा है तथा इस अवस्था में उपयोगी गुणवत्तायुक्त औषधियों का वितरण भी किया जा रहा है।

नए संस्थानों का निर्माण और सुविधाओं का विकास हुआ

6 शहरों में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के महाविद्यालय शुरू हुए

राजस्थान में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के प्रचार-प्रसार व इससे संबंधित सुविधाओं को विकसित करने के लिए गहलोत सरकार ने पिछले करीब साढ़े चार साल में हर संभव प्रयास किए हैं।

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के 6 जिलों में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा के एकीकृत नए महाविद्यालय प्रारंभ किए हैं। ये महाविद्यालय जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और सीकर में खोले गए हैं। इन महाविद्यालयों की स्थापना से इस पद्धति का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है।

नए महाविद्यालयों की स्थापना के साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के नवीन अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। महाविद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति के साथ ही 750 शैक्षणिक व अशैक्षणिक नवीन पदों का सृजन हुआ जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

और भी नए संस्थान...

राजस्थान सरकार के प्रयासों से तारानगर-चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय और भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं, केकड़ी-अजमेर और जोधपुर में नवीन होम्योपैथिक महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। उदयापुर के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के संबद्ध चिकित्सालय में गहलोत सरकार ने 50 बैड की वृद्धि की है और 6 नए स्नातकोत्तर विभागों में पाठ्यक्रम शुरू करवाए गए।

वहीं, एक औषधालय को चिकित्सालय में और दो औषधालय/चिकित्सालय को ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया।

प्रदेश के 2 शहरों में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय

वर्तमान राज्य सरकार ने आयुष क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाते हुए उदयपुर और जोधपुर में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किए हैं। वहीं, विद्यार्थियों को बेहतर आवास देने के उद्देश्य से जोधपुर के डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्र-छात्रावास का लोकार्पण किया गया। उधर नवीन स्नातकोत्तर महिला छात्रावास भवन, इन्टरनेशनल सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन पंचकर्मा, औषध गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना एवं रसायनशाला का विस्तार आदि कार्यों को शुरू किया गया।

राजस्थान सरकार आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और विकास को भी बढ़ावा दे रही है। इस उद्देश्य के साथ सरकार ने केकड़ी (अजमेर) में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर संचालन शुरू किया है। राजस्थान में औषधियों के निर्माण में भी बढ़ोतरी हुई है। राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला द्वारा 65.51 करोड़ रुपए की औषधियों का निर्माण कर चिकित्सालयों/औषधालयों में वितरण किया गया है। वहीं नाथद्वारा - राजसमंद में मेडि ट्यूरिज्म वैलनेस सेन्टर स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

मेडि ट्यूरिज्म वैलनेस सेंटर : सेहत की नई शुरुआत

निरोगी राजस्थान अभियान के अन्तर्गत राज्य के पर्यटन एवं धार्मिक स्थानों पर आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जा रही है ताकि आम लोगों का आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति रुझान बढ़ सके।

राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थानों पर 50 से 100 बीघा भूमि पर प्राकृतिक वातावरण में वैलनेस सेन्टर एवं योग केंद्र, आयुर्वेद विभाग के माध्यम से खोले जा रहे हैं। जिससे राज्य में मेडि ट्यूरिज्म को बढ़ावा मिल सके एवं धार्मिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को इन चिकित्सा सुविधाओं का अधिक लाभ मिल सके। इन केंद्रों पर आगन्तुक पर्यटकों के लिए सुव्यवस्थित, सुसज्जित व आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास सुविधा के साथ-साथ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

बेहतर इम्युनिटी पर जोर • प्रदेश के हर घर में तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय

घर-घर औषधि योजना के जरिए राजस्थान को स्वस्थ बना रही राज्य सरकार, 519 लाख पौधे वितरित किए

राज्य के लोगों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में घर-घर औषधि योजना चला रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 में अपने निवास पर गिलोय का पौधा लगाकर घर-घर औषधि योजना की शुरुआत की। प्रदेश भर में योजना के तहत तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय के पौधे घरों तक पहुंचाए गए। योजना में प्रदेशभर में 518.78 लाख औषधीय पौधे लगभग 65 लाख परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध करवाये गए।

एक परिवार को आठ पौधे

वर्ष 2022-23 से इस योजना के तहत एक परिवार को अधिकतम 8 पौधे दिए गए। साथ ही परिवार को चार प्रकार (गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ) के दो-दो पौधों के स्थान पर किन्हीं भी दो प्रकार के चार-चार पौधे लेने का विकल्प उपलब्ध करवाया गया। पौधों का वितरण यथासम्भव वन विभाग की नर्सरियों से किया गया। वर्ष 2022-23 में 127.01 लाख पौधों का वितरण किया गया।

रिसर्च में प्रमाणित ज्ञान के बाद पौधों को योजना में शामिल किया गया

- **राजस्थान** संभवतः पहला प्रदेश है, जिसने औषधीय पौधों के प्रति जन चेतना जागृत करने के लिए वृहद स्तर पर ऐसी अनूठी योजना लागू की। यह भावी पीढ़ी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है।
- **योजना** में चारों प्रजातियों के पौधों को 11 हजार से अधिक रिसर्च पेपर और 350 क्लीनिकल ट्रायल्स पर आधारित प्रमाणित ज्ञान के बाद शामिल किया गया।

प्रदेश में 100 आयुष चिकित्सालयों और औषधालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विकास एवं विस्तार के लिए निरन्तर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 आयुष चिकित्सालयों और औषधालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, इन सुविधाओं के संचालन के लिए कुल 200 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी।

जयपुर में 18, जोधपुर में 16, भरतपुर में 8, सीकर में 6, अजमेर व सवाईमाधोपुर में 5-5, उदयपुर, दौसा व झुंझुनूं में 4-4, नागौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व चूरू में 3-3, कोटा, जालोर, जैसलमेर व राजसमंद में 2-2, अलवर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर, हनुमानगढ़, करौली, पाली, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर व टोंक में 1-1 आयुष चिकित्सालय/औषधालय में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

- प्रथम चरण में 500 आयुर्वेद औषधालयों को आयुष हैल्थ एंड वैलनेस सेन्टर के रूप में 50.65 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया।
- इनमें 496 पुरुष एवं 467 महिला योग प्रशिक्षकों को नियुक्ति किया गया।
- द्वितीय चरण में 500 अन्य आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी औषधालयों को आयुष हैल्थ एंड वैलनेस सेन्टर के रूप में विकसित किया जा रहा।
- इनमें 432 पुरुष एवं 370 महिला योग प्रशिक्षकों को नियुक्ति किया गया।
- सीकर जिला मुख्यालय पर 50 शैय्याओं के एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्थापना।
- टोंक स्थित यूनानी महाविद्यालय के भवन का लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार।
- राज्य सरकार द्वारा 179 आयुर्वेद / होम्योपैथिक / यूनानी औषधालय भवनों के निर्माण / मरम्मत कार्य पर 26.27 करोड़ रुपए व्यय किए।
- राज्य में 9 पौधशालाएं (3 मॉडल व 6 स्मॉल) विकसित।

▪ स्पेशल इनिशिएटिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग